सिलावट और सिंघार बने सुर्खियां....

विशेष प्रतिनिधि

इंदौर. मालवा -निमाड़ में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है. भारतीय जनता पार्टी जहां,अपने अंदरूनी संगठन चुनाव करवाने में व्यस्त है. वहीं कांग्रेस में झाबुआ उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर तेज सरगर्मियां हैं. इस सबके बीच प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री तुलसीराम सिलावट और उमंग सिंघार अलग-अलग कारणों से सुर्खियों में बने हुए हैं.

सिंधिया समर्थक प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार

सिंघार का मामला अनुशासन समिति में तो सिलावट की दिग्विजय से मुलाकात ने राजनीतिक हलचल पैदा की

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट प्रदेश के अत्यंत वरिष्ठ दलित नेता माने जाते हैं. वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं. मंत्री बनने के बाद वे पहली बार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया. इसके बाद इंदौर नेत्र चिकित्सालय के आंख फोडवा कांड में जिस तरह उन्होंने त्वरित कार्रवाई की. उसकी प्रशंसा सर्वत्र हुई. उन्हें प्रदेश के मीडिया ने हाथ हाथों हाथ लिया. श्री

सिलावट एक बार फिर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. इस बार मामला उनके विभाग का या सरकारी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर का है. हाल ही में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से बंद कमरे में करीब 40 मिनट तक चर्चा की. इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई होगी. इसको लेकर अलग-अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं.

इधर युवा आदिवासी मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहे उमंग सिंघार पर चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि उनके बयानों का संज्ञान कांग्रेस आलाकमान ने लिया है.

पार्टी नेतृत्व ने इन बयानों को पार्टी के लिए नुकसानकारी मानते हुए समूचा मामला केंद्रीय अनुशासन समिति को सौंप दिया है. सनद रहे केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री एके एंटोनी हैं.

उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने के कारण चर्चा में आए थे. हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ के समझाने पर वे मान गए. मुख्यमंत्री के सख्त रुख को देखते हुए पिछले सप्ताह बरसे मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे चर्चा में लगातार बने हुए हैं.

यह संयोग नहीं है कि सुर्खियों में बने दोनों मंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं. यह भी संयोग नहीं है कि, दोनों को सुर्खियां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कारण मिली हैं.

उपचुनाव के लिए हिमाचल भाजपा ने कसी कमर

शिमला. विधानसभा उपचुनाव के लिए हिमाचल भाजपा ने अपनी कमर कस ली है. धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे चुनावों की तैयारियों के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने शिमला पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की नब्जें टटोलीं. शनिवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी के शिमला पहुंचने पर होटल पीटरहॉफ शिमला में एक बैठक हुई. इस बैठक में जहां भाजपा के राज्य प्रभारी मंगल पांडे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने इस बैठक की अध्यक्षता की. प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद रामस्वरूप शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त, प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर, राम सिंह, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और विस्तारक भी उपस्थित रहे.

इस मौके पर हुई चर्चा में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए जल्द ही संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने पर सहमति बनी. ऐसे प्रत्याशियों पर मंडल और जिला कमेटियों से फीडबैक लेने को कहा गया जो जिताऊ हैं.

प्रभारी ने एकजुटता की सीख दी

भाजपा के मंत्री रहे किशन कपूर के सांसद बनने से धर्मशाला और विधायक सुरेश कश्यप के सांसद बनने से पच्छाद सीटें खाली हुई हैं. उपचुनाव पर चर्चा के लिए दूसरे दौर की बैठक भी हुई. प्रभारी मंगल पांडे के साथ भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने विधानसभा उपचुनाव की आगामी तैयारियों पर चर्चा की. सूत्रों ने बताया कि इस मौके पर प्रभारी मंगल पांडे ने पिछले दिनों भाजपा संगठन में मचे घमासान पर कड़ा संज्ञान लिया और भाजपा नेताओं को एकजुटता की सलाह दी.

नीतीश झारखंड में क्यों बीजेपी पर कस रहे तंज

नई दिल्ली. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रांची दौरे पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेताओं से कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है. बता दें कि झारखंड में बीजेपी सहयोगी पार्टी है, जहां रघुवर दास की सरकार है. नीतीश कुमार ने राज्य में ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि अविभाजित बिहार से निकले राज्य ने उस तरह

नीतीश ने कहा अविभाजित बिहार से निकले राज्य ने वैसी प्रगति नहीं की है, जैसी अपेक्षा थी

भाजपा राज्य की 81 विस सीटों में से 65 पर जीत हासिल करने के मिशन पर चल रही

से प्रगति नहीं की है, जिस तरह की अपेक्षा थी. उन्होंने बीजेपी सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार से लोग झारखंड में शराब के लिए आते हैं. झारखंड में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इन बयानों को राज्य में अपनी पार्टी की विस्तार योजनाओं के रूप में देखा जा रहा है.

यह हैं तंज कसने के कारण

पहला कारण- नीतीश कुमार की

पार्टी जनता दल (युनाइटेड) झारखंड में अपना खोया हुआ गौरव हासिल करना चाहती है. साल 2005 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में जद (यू) ने 4 फीसदी वोट हासिल किए थे और 6 विधानसभा सीटें जीती थीं. साल 2009 में जदयू की दो सीटें कम हो गईं और वोट फीसदी में गिरावट होकर 2.8 फीसदी ही रह गई. वहीं 2014 में नीतीश की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और वोट फीसदी महज 1 फीसदी पर आ पहुंचा.

दूसरा कारण- झारखंड कभी अविभाजित बिहार का हिस्सा था और जदयू का ऐसा मानना है कि राज्य में ब्रांड नीतीश काफी अहम है. पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने पहले ही पार्टी कैडर से कह दिया है कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को भविष्य के चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ट्रीट करें.

तीसरा कारण-अन्य पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी को देखते हुए जदयू का मानना है कि नीतीश कुमार की ओबीसी साख इन समुदायों का बहुत समर्थन हासिल कर सकती है. झारखंड में ओबीसी भाजपा के पारंपरिक समर्थक रहे हैं और ऐसे में जदयू इस अवसर को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में है.

चौथा चरण- सही से राजनीतिक हलचल को देखा जाए तो जदयू चाहेगा कि भाजपा झारखंड में भी इसके लिए कुछ सीटें छोड़ दे. लेकिन भाजपा राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 65 पर जीत हासिल करने के मिशन पर चल रही है. इसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा. पूर्व मंत्री सुदेश महतो के नेतृत्व वाले स्थानीय संगठन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ भाजपा का पहले से ही गठबंधन है. इसने नीतीश कुमार के लिए झारखंड के लिए राजग में जगह कम कर दी है. वहीं, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी यहां एक-दो सीटें मांग रही है.

घर-घर रघुबर अभियान पर भाजपा में रार

रांची. झारखंड विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है. चुनाव की तारीखों का इसी महीने ऐलान होने की संभावना है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाने के लिए, तो वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) समेत अन्य विरोधी पार्टियां भाजपा को शिकस्त देकर सत्ता में वापसी करने के लिए

राय का निशाना रघुवर दास

तैयारी में जुटी हैं.

इन सबके बीच झारखंड में भाजपा का घर-घर रघुबर अभियान शुरू होने से पहले ही पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई. नौ सितंबर को शुरू इस अभियान का नाम बदलने की मांग उठने लगी है. पार्टी के वरिष्ठ नेता

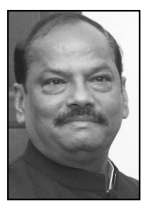

और रघुबर सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर इस अभियान का नाम बदलने की मांग भी कर दी है. राय ने ट्वीट किया है कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ से दूरभाष पर बात हुई. उन्हें सलाह दी कि चुनावी दृष्टि से जनसंपर्क अभियान का नारा घर-घर कमल तय करें. राय ने लिखा है कि यह वाक्य केवल नारा नहीं होगा बल्कि निष्ठा का प्रतीक भी होगा. मेरा यह सुझाव उन्हें अच्छा लगा.

नाम लिए बगैर साधा रघुवर पर निशाना: मंझे सियासतदां राय ने कुछ घंटों बाद ही एक और ट्वीट किया. राय ने अपने अगले ट्वीट में तुकबंदी करते हुए लिखा, घर घर भाजपा, घर घर कमल. बाद में मैं, पहले दल.

हालांकि इस ट्वीट में भी सरयू राय ने अपने मुख्यमंत्री का जिक्र करना तो दूर, नाम का कहीं उल्लेख तक नहीं किया, लेकिन नारे को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि राय का निशाना रघुवर दास ही हैं.

आसान नहीं रघुवर की राह: भाजपा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि वह मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी. झारखंड भाजपा के इस अभियान को रघुवर के नेतृत्व पर मुहर माना जा रहा था. पार्टी द्वारा बगैर घोषणा के अप्रत्यक्ष संदेश को अंतर्कलह से बचने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

बसपा-कांग्रेस के तालमेल की कितनी संभावना

हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का तालमेल एक बार फिर खत्म हो गया है. पार्टी प्रमुख मायावती ने राज्य में नई बनी जननायक जनता पार्टी के साथ अपना तालमेल खत्म कर लिया है.

मायावती ने राज्य में नई बनी जननायक जनता पार्टी के साथ अपना तालमेल खत्म किया

यह तालमेल लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था. उस समय मायावती ने ओमप्रकाश चौटाला और उनके छोटे बेटे के नियंत्रण वाली इनेलो के साथ

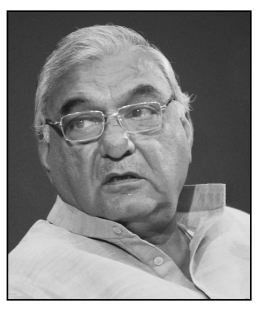

तालमेल खत्म करके दुष्यंत चौटाला की बनाई नई पार्टी से तालमेल किया था. पर अब उन्होंने उनसे भी तालमेल खत्म कर लिया है. तभी यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे कांग्रेस के साथ तालमेल कर सकती हैं. कांग्रेस इसके लिए काफी समय से प्रयास कर रही है और हाल ही में उसने कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना कर फिर दलित नेतृत्व आगे किया है.

ध्यान रहे पिछले कुछ दिनों से इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि भूपेंदर सिंह हुड्डा अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो वे मायावती के साथ तालमेल की बात कर सकते हैं. वे मायावती की हर मांग पूरा करने में सक्षम हैं. पर अब स्थितियां बदल गई हैं. अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने का इरादा त्याग दिया है.

मायावती के पास भी अब कोई ज्यादा विकल्प नहीं हैं क्योंकि वे इनेलो, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथ तालमेल करके खत्म कर चुकी हैं और भाजपा उनके साथ तालमेल करेगी नहीं. सो, या तो उन्हें अकेले लड़ना होगा या कांग्रेस से तालमेल करना होगा. कांग्रेस की ओर से भी इसके लिए प्रयास किया जाएगा.

हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ेगी बसपा

लखनऊ. हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है. मायावती ने एक ट्वीट कर कहा, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके हिसाब से हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में दुष्यन्त चौटाला की पार्टी से जो समझौता किया था, वह सीटों की संख्या व उसके आपसी बंटवारे के मामले में उनके अनुचित रवैये के कारण बीएसपी हरियाणा यूनिट के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पार्टी हाईकमान ने यह फैसला किया है कि हरियाणा प्रदेश में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा आमचुनाव में अब बसपा अपनी पूरी तैयारी के साथ अकेले ही यहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

ज्ञात हो कि हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है. क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) पहले ही दो फाड़ हो चुकी है. इसी से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पौते दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी (जजपा) का गठन किया है.

प्रियंका को मिल सकता है पूरे यूपी कांग्रेस का प्रभार

नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी नई जिम्मेदारी दे सकती है. सूत्रों के अनुसार, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि प्रियंका को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभार दे दिया जाए. अब वो प्रदेश के पूर्वी हिस्से की प्रभारी हैं और पश्चिमी हिस्सा ज्योतिरादित्य के जिम्मे है. लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद से अब तक लगातार कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर चल रहा है. राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था. इसके बाद से पार्टी के लिए नए अध्यक्ष की तलाश जारी है.

दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के प्रयास

दिल्ली. सेक्यूलर वोटों का विभाजन टालने के लिए अब महाराष्ट्र कांग्रेस व एनसीपी के कई प्रमुख नेताओं ने अपनी - अपनी सीट पर व्यापक प्रबंधन का फार्मूला अपनाना शुरू कर दिया है. सुर्खियों में रहने वाले कई नेताओं ने दलित

मजबूत जेब वाले कुछ प्रमुख नेताओं ने अपनी-अपनी सीटों की फिक्र करनी शुरू कर दी

और मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के लिए यह प्रयास पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ कर रखा है और उसमें कईयों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है.

पार्टी के स्तर पर पूरे प्रदेश में एक व्यापक गठबंधन बनाने की गंभीर कोशिश कांग्रेस के नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया था. उसी तर्ज पर कोशिश इस बार भी प्रारंभ की गई, लेकिन अभी तक सिरे चढ़ता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. 2014 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने खासकर विदर्भ व मराठवाड़ा की बहुत सारी सीटों पर तकलीफ दी थी, तो एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम बेल्ट में काफी चोट पहुंचाई थी. हाल के लोकसभा चुनाव में एमआईएम तो औरंगाबाद की सीट जीत पाने में सफल रही, लेकिन हारने के बावजूद प्रकाश आंबेडकर ने काफी वोट खींचे. इनके साथ

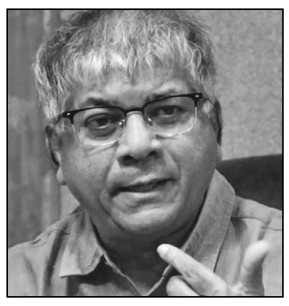

राज्यव्यापी सौदा भले ही ना पटे, लेकिन मजबूत जेब वाले कुछ प्रमुख नेताओं ने अपनी-अपनी सीटों की फिक्र करनी शुरू कर दी है और वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम इन प्रमुख तीन पार्टियों की ओर से इन वर्गों के मजबूत चेहरे उनके खिलाफ न उतरें. पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह रुझान भी सामने आया है कि भाजपा नेतृत्व विपक्षी वोटों में बंटवारा करने के लिए कई नवगठित दलों के उम्मीदवार के रूप में या निर्दलीय हैसियत से ही समाज के उन तबकों के प्रत्याशियों को खड़ा होने की प्रेरणा देता है, जिनके वोट आमतौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जाते हैं.

कांग्रेस के यह चुनिंदा नेता इस समय यह प्रयास करने में जुटे हैं कि उन्हें वोट दे सकने वाले वर्गों के मजबूत चेहरे इस चक्कर में न पड़ें. जब नामांकन भरने की प्रक्रिया खत्म होगी, तब जाकर पता चलेगा कि कांग्रेस और एनसीपी के कौन-कौन नेतागण अपनी सीटों की पुख्ता किलेबंदी कर पाए हैं?

15 तारीख से पहले हो सकती है पहली सूची स्वीकृत

दिल्ली. महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए पार्टी की छानबीन समिति 10 तारीख से लगातार तीन दिन बैठने जा रही है. ऐसा लग रहा है कि इस बार वह अपना काम पूरा खत्म करके रहेगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है. राज्य के प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खरगे के नजदीकी सूत्रों ने संकेत दिया है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 15 तारीख से पहले हो सकती है और उसमें पहली सूची को स्वीकृति मिल जाएगी, जिसमें 75 से अधिक नाम हो सकते हैं.

सूत्रों के अनुसार समिति ने वैसी 120 सीटें छांट रखी हैं, जहां कांग्रेस अधिक संसाधन और ताकत लगाएगी, क्योंकि उनमें ही जीत की संभावना अधिक नजर आ रही है. वैसे तो एनसीपी व अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाने वाली सीटों को भी चिन्हित किया गया है, लेकिन पार्टी के एक नेता ने संकेत दिया कि सभी 288 सीटों पर नामों के पैनल तैयार रखे जा रहे हैं. ताकि, यदि 2014 की तरह अचानक कोई झटकेदार स्थिति पैदा हो, तो उससे भी निपटा जा सके.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह जब छानबीन समिति की पहली बैठक हुई थी, तो अगले 20 दिनों का रोडमैप तैयार कर लिया गया था. राज्य के सभी प्रमुख नेताओं से मशविरा हो जाने के बाद अब समिति के सदस्य आपस में मंथन कर रहे हैं. एनसीपी से बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्रीगण अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार की टीम लगी हुई है. 2014 में अलग-अलग चुनाव

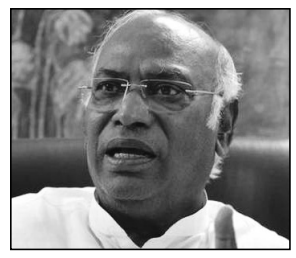

समिति के सदस्य आपस में कर रहे मंथन

लड़ते समय जिन सीटों पर एनसीपी आदि से कांग्रेस आगे थी, वैसी 110 सीटें छांटकर इन नेताओं ने छानबीन समिति को बता दिया है और फिलहाल उन पर ही प्रत्याशी फाइनल किए जा रहे हैं. पहली सूची में भी इनमें से ही ज्यादातर नाम होंगे. एनसीपी के लिए अभी तक 105 सीटें निकली हैं.

प्रकाश आंबेडकर के साथ तालमेल की कोशिश अंतिम समय तक जारी रखी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आघाड़ी की तुलना में युति ने जो एक करोड़ वोट अधिक प्राप्त किए हैं, उनमें से 30त्न की भरपाई प्रकाश के सहयोग से हो सकती है. कांग्रेस के नेतागण अपने यहां से और एनसीपी से भाजपा- शिवसेना की ओर जाने वालों की लगी हुई लाइन से परेशान तो हैं, लेकिन फिर भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो वोट मोदी के नाम पर एनडीए को गया, उसमें से कम से कम 30 से 40 लाख वोट वे विधानसभा चुनाव में वापस अपनी ओर खींच पाएंगे. चुनाव के स्थानीय होने और साथ में उम्मीदवार व उसकी जाति के आधार पर ऐसा करने की कोशिश चल रही है. उनका आकलन है कि यदि वास्तव में ऐसा हो पाता है, तो दोनों गठबंधनों में कांटे की टक्कर हो जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए 10 तारीख को छानबीन समिति आगे की काट - छांट शुरू करेगी.

10000 से कम वोटों से हारे नेताओं को मैदान में उतारने पर विचार

कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपने उन नेताओं को फिर से मैदान में उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जो पिछली बार भाजपा की आंधी में 10000 से कम वोटों से हारे थे. बताया जा रहा है कि ऐसी सूची बना ली गई है और छानबीन समिति की 5 तारीख को हुई बैठक में प्रदेश इकाई से इन नेताओं की वर्तमान स्थिति और उनकी इच्छा के बारे में भी फीडबैक ले लिया गया है. उनकी टिप्पणियों के साथ इन सीटों का विवरण केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जा रहा है. कुछ स्थान पर हारे हुए नेता से पूछ कर उनके परिजन भी उतारे जा सकते हैं. मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कृपाशंकर सिंह 2014 में कलीना सीट से तीसरे स्थान पर रहे तो थे, लेकिन वे हारे 10000 से कम वोटों से थे. भायखला में मधु चव्हाण , पेण में रवि सेठ पाटिल, जालना में कैलाश गोरंटियाल, परतूर में सुरेश जेठालिया, राजूरा में सुभाष धोटे और शहादा में पद्माकर वलवी तो केवल 5000 के भीतर हारे थे. दस हजार के भीतर हारने वाले अन्य नेताओं में कोल्हापुर दक्षिण सीट से मंत्री रहे सतेज बंटी पाटिल, खामगांव से दिलीप सानंदा, बालापुर से सैयद नतीकुद्दीन खतीब, वर्धा से शेखर शेंडे, वणी से वामनराव कासावार, देगलूर से रावसाहेब अंतापुरकर, रावेर से शिरीष चौधरी, भिवंडी पश्चिम से शोएब खान, पुरंदर से संजय जगताप और करवीर से पीएन पाटिल शामिल थे .

विशेष

निकाय चुनाव : बीजेपी-कांग्रेस ने शुरू की मोर्चाबंदी

जयपुर. विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद अब बीजेपी-कांग्रेस ने प्रदेश में नवंबर में होने वाले निकायों चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है. बीजेपी ने दावा किया है कि केन्द्र सरकार के कार्यों के दम पर निकायों में उनकी सरकार बनेगी. वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य सरकार के कार्यों के जरिए वे निकायों की सत्ता पर काबिज होंगे.

188 से बढ़कर 193 हुए निकाय

प्रदेश में अभी तक 188 निकाय थे, लेकिन परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 193 हो गई है. खाटूश्यामजी, थानागाजी, महुआ, नसीराबाद और परतापुरगढ़ नए निकाय बने हैं. निकाय चुनाव 3 चरण में होने हैं. पहले चरण में 51 निकायों के चुनाव नवंबर माह में होना प्रस्तावित है. इनमें 25 जिलों की 64 विधानसभा क्षेत्रों में निकाय चुनाव होंगे. इस चरण में अजमेर को छोड़ कर 6 नगर निगमों में भी चुनाव होंगे.

बूथ मैनेजमेंट के दम पर तैयारियां शुरू की

निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने जिला संगठन प्रभारी और बूथ प्रबंधन

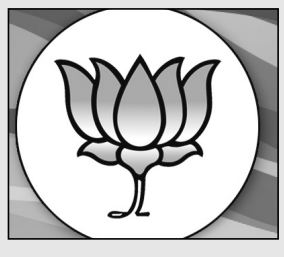

अधिकारी समेत निकाय चुनाव में अनुभव रखने वाले नेताओं को जिम्मेदारी दी है. बीजेपी इस बार चुनाव में केन्द्र सरकार के कार्यों के अलावा स्थानीय मुद्दों को निकाय चुनाव में प्रमुखता से रखने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही वह कश्मीर से अनुछेच्द-370 और 35ए के मुद्दे को भी भुनाएगी. बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट के दम पर

अपनी तैयारियां शुरू कर दी है.

कांग्रेस ने हटाया शैक्षणिक योग्यता का बैरियर

दूसरी तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस ने लगभग एक सप्ताह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक कर निकाय चुनाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है. कांग्रेस राज्य सरकार के कामकाज के दम पर निकाय चुनाव में जीत का दाव खेल रही है. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व किए गए वादे के मुताबिक निकाय चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता का बैरियर पहले ही हटा दिया है. वह इसको भुनाने के साथ ही बजट की घोषणाओं को भी निकाय चुनाव में जनता के बीच जाएगी. निकाय चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू जरुर कर दी है, लेकिन शहरी सरकार का सेहरा जनता किसके सर बाधेंगी यह तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चल पाएगा.